



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 323] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 27, 1986/आषाढ़ 6, 1908
No. 323] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 27, 1986/ASADHA 6, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

यिस्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(विवेक कर विभाग)

नई दिल्ली, 27 जून, 1986

प्रधिसूचना

प्रायकर

(1964 का 7) की धारा 24क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए, निवेदन देती है कि उक्त अधिसूचना के सभी उपबन्धों को भारत के
संघ में प्रभावी किया जाएगा।

भारत गणराज्य की सरकार और बाईलैंड राज्य की सरकार के बीच
प्राय पर दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व के प्रपबंधन को
रोकने के लिए अधिसूचना

भारत गणराज्य की सरकार और

बाईलैंड राज्य की सरकार

प्राय पर दोहरे कराधान के परिहार और

राजस्व के प्रपबंधन को रोकने के लिए

अधिसूचना सम्पन्न करने की इच्छा से

नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई है:

सा. का. नि. 915(अ)—प्राय पर कर की बाबत दोहरे कराधान का परिवर्जन
और राजवित्तीय प्रपबंधन के निवारण के लिए भारत गणराज्य की सरकार
तथा बाईलैंड मा.राज्य की सरकार के बीच हुए संलग्न अधिसूचना का
अनुसमर्थन हो गया है तथा उक्त अधिसूचना के अनुच्छेद 28 द्वारा अपेक्षित
के अनुसार अनुसमर्थन की तिथियों का 13 मार्च, 1986 को आदान-
प्रदान हो गया है;

अन., केन्द्रीय सरकार, प्राय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का
43) की धारा 90 और कंपनी (ला.) अधिनियम, 1964

अध्याय I

अभिसमय का क्षेत्र-विस्तार

अनुच्छेद 1

व्यक्ति क्षेत्र

यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो किसी एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी हैं।

अनुच्छेद 2

अभिसमय के अन्तर्गत आने वाले कर

1. यह अभिसमय प्रत्येक संविदाकारी राज्य अथवा उसके राजनीतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकारों की ओर से आय पर लगाये जाने वाले करों पर लागू होगा, चाहे वे कर किसी भी तरह से लगाये जाते हों।

2. कुल आय, अथवा आय के तत्वों पर लगाये गये करों की आय पर करों के रूप में माना जाएगा जिसमें चल अथवा चल संपत्ति के अन्तर्गत से हुए अभिलेखों पर लगाये जाने वाले कर और उद्यमों द्वारा अथवा की गई मजदूरी अथवा वेतन की कुल रकमों पर लगने वाले कर भी शामिल हैं।

3. यह अभिसमय जिन वर्तमान करों पर लागू होगा वे हैं:—

(क) भारत के मामले में

(i) आयकर, जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अन्तर्गत उस पर लगाया जाने वाला कोई भी अधिभार शामिल है; और

(ii) कंपनी (लाभ) अधिकार अधिनियम, 1964 (1964 का 7) के अन्तर्गत लगाया जाने वाला अधिकार,

(जिसे इसके पश्चात् "भारतीय कर" कहा गया है);

(ख) बाईलैण्ड के मामले में:

(i) आयकर; और

(ii) पैट्रोलियम आयकर,

(जिसे इसके पश्चात् "बाई कर" कहा गया है)।

4. यह अभिसमय किन्हीं समरूप अथवा सारतः वैसे ही करों पर भी लागू होगा जो इस अभिसमय पर हस्ताक्षर की तारीख के पश्चात् इस अनुच्छेद के पैरा 3 में उल्लिखित करों के अनुरूप अथवा उनके स्थान पर लगाये जाते हैं। संविदाकारी राज्यों के संसद प्राधिकारी अपने-अपने कानूनों में किये गये महत्वपूर्ण परिवर्तनों से एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे।

अध्याय II

परिभाषाएँ

अनुच्छेद 3

सामान्य परिभाषाएँ

1. इस अभिसमय के उद्देश्यों के लिये, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) "भारत" शब्द में अभिप्रेत है, भारत का राज्य क्षेत्र और उसमें शामिल है राजकीय सन्तुद्र और उसके ऊपर का आकाशी क्षेत्र तथा राजकीय सागर खण्ड महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अन्य आर्थिक-क्षेत्र और समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्यांक 80) में उल्लिखित कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल है जिसमें भारत के प्रभुता-सम्पन्न अधिकार हों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार जिस सीमा तक

उनमें इन अधिकारों का प्रयोग इस तरह से किया जा संकेत है कि मानो इस प्रकार का समुद्री क्षेत्र भारत के राज्य-क्षेत्र का एक हिस्सा है;

(ख) "बाईलैण्ड" शब्द में अभिप्रेत है बाईलैण्ड का राज्य क्षेत्र उसमें बाईलैण्ड के राज्य के राजकीय सन्तुद्र से लगा वह कोई भी समुद्री क्षेत्र शामिल है जो बाई कानून, और अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा ऐसे क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया गया है अथवा इसके बाध निर्दिष्ट किया जा सकेगा जिसके अन्तर्गत बाईलैण्ड के राज्य के अधिकारों का प्रयोग किया जा सके;

(ग) "एक संविदाकारी राज्य" और "दूसरा संविदाकारी राज्य" पदों से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार भारत अथवा बाईलैण्ड अभिप्रेत है;

(घ) "कर" पद से, संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार, भारतीय कर अथवा बाई कर अभिप्रेत है;

(ङ) "व्यक्ति" पद में कोई व्यक्ति, कंपनी और कोई अन्य सत्ता शामिल है जिसे अलग-अलग संविदाकारी राज्यों में लागू कराधान कानूनों के अधीन कर लगने योग्य एकक के रूप में समझा जाता है;

(च) "कम्पनी" पद से कोई भी ऐसा निगमित निकाय अथवा कोई ऐसी इकाई अभिप्रेत है जो अलग-अलग संविदाकारी राज्यों में लागू कराधान कानूनों के अधीन कंपनी अथवा निगमित निकाय के रूप में मानी जाती है;

(छ) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" पदों से क्रमशः, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित उद्यम अभिप्रेत है;

(ज) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, भारत के मामले में, केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अथवा उनका प्राधिकृत प्राधिकारी; और बाईलैण्ड के मामले में वित्त मंत्री अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि;

(झ) "राष्ट्रिक" पद से अभिप्रेत है संविदाकारी राज्य की राष्ट्रिकता धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति और कोई भी विधिक व्यक्ति, भागीदारी, संस्था और संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से अपनी हैसियत प्राप्त करने वाली कोई अन्य सत्ता;

(ञ) "अन्तर्राष्ट्रीय मातायास" पद से अभिप्रेत है, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा परिचालित किसी जलयान या वायुयान द्वारा किया जाने वाला परिवहन, सिवाय ऐसी स्थिति के जहाँ जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच परिचालित किये जाते हों।

2. संविदाकारी राज्यों में से एक संविदाकारी राज्य द्वारा इस अभिसमय के उपबन्धों को लागू करने में, किसी भी पद का जो यहाँ परिभाषित नहीं हुआ हो, संदर्भ में जब तक अन्यथा अपेक्षा नहीं हो, तब तक वही अर्थ होगा जो उसका उस संविदाकारी राज्य के उन करों के संबंध में प्रवृत्त कानूनों के अन्तर्गत होता है जो इस अभिसमय के विषय हैं।

अनुच्छेद 4

निवासी

1. इस अभिसमय के प्रयोजनों के लिये, "संविदाकारी राज्य का निवासी" पद से अभिप्रेत है, ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो उस राज्य के कानूनों के अधीन, अपने अधिवास, निवास, निगमिकरण का स्थान, प्रवृत्त का स्थान या इसी प्रकार की किसी अन्य कसौटी के कारण, उसमें कर लगने योग्य है।

2 जहाँ पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के कारण, कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो इस अभिसमय के प्रयोजनों के लिए उसको निवासी हैसियत निम्नलिखित नियमों के अनुसार निश्चित की जाएगी:—

(क) उसे उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जहाँ उसे कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो। यदि उसे दोनों संविदाकारी राज्यों में स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं (जिसे इसके बाद उसका "महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र" के रूप में उल्लिखित किया जाएगा);

(ख) यदि उस संविदाकारी राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र है, निश्चय नहीं किया जा सकता हो, अथवा यदि उसे किसी भी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें वह आमतौर पर रहता हो;

(ग) यदि वह दोनों संविदाकारी राज्यों में आमतौर पर रहता है अथवा इनमें से किसी में भी नहीं रहता है, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह राष्ट्रिक है;

(घ) यदि वह दोनों संविदाकारी राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे।

3 जहाँ पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के कारण, व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति, दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी प्रश्न को पारस्परिक सहमति से स्तय करेंगे।

अनुच्छेद 5

स्थायी संस्थापन

1 इस अभिसमय के प्रयोजन के लिए "स्थायी संस्थापन" पद का अर्थ होगा कारोबार का वह निश्चित स्थान जिसके माध्यम से उद्यम का कारोबार पूर्णतः अथवा अंशतः किया जाता है।

2 "स्थायी संस्थापन" में निम्नलिखित शामिल होंगे:—

- (क) प्रबंध का कोई स्थान;
- (ख) कोई शाखा;
- (ग) कोई कार्यालय;
- (घ) कोई कारखाना;
- (ङ) कोई कार्यशाला;
- (च) कोई खान, कोई खदान, तेल अथवा गैस का कोई कुंआ, अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान;
- (छ) फार्म, बाग अथवा ऐसा अन्य स्थान जहाँ कृषि, वन संपत्ति, बागवान अथवा उनसे संबंधित कार्यकलाप किये जाते हैं;
- (ज) कोई भवन स्थल अथवा निर्माण-कार्य, संयोजन-परियोजना अथवा उससे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यवाही, जहाँ इस प्रकार का स्थल, परियोजना या कार्यवाही उसी अथवा किसी संबंधित परियोजना के लिये कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक की अवधि अथवा अवधियों के लिये जारी रहती हो;
- (झ) दूसरों का भण्डारण की भविष्य में देने वाले व्यक्ति से संबंधित कोई मास गोवाय;

(त) एक संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा कर्मचारियों अथवा दूसरे कामियों के जरिये सेवायें प्रस्तुत करना, जिसमें परामर्शदात्री सेवायें भी शामिल हैं, वगैरें कि उग प्रकार के कार्य (जसी अथवा उससे संबंधित किसी परियोजना के लिए) दूसरे संविदाकारी राज्य में कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक की अवधि अथवा अवधियों के लिये जारी रहते हों।

3 इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा:

- (क) किसी उद्यम के मास अथवा तिजारती मास के केवल भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का प्रयोग;
- (ख) केवल भण्डारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ उद्यम के मास अथवा तिजारती मास का स्टॉक रखना;
- (ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किये जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के मास अथवा तिजारती मास का स्टॉक रखना;
- (घ) किसी उद्यम के लिए मास अथवा तिजारती मास का केवल क्रय करने अथवा सूचना एकत्र करने के प्रयोजनार्थ कारखाने का कोई निश्चित स्थान रखना;
- (ङ) उद्यम के लिए, अनन्य रूप से विभाजन देने, सूचना प्रदान करने, वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा ऐसे ही अन्य कार्यकलापों के लिये, जो प्रारंभिक अथवा सहायक स्वरूप के हों, कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना।

4 पूर्ववर्ती पैराग्राफों के उपबंधों के होते हुए भी, दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से एक संविदाकारी राज्य में कार्य कर रहा कोई ऐसा व्यक्ति (जो दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत के किसी भी अन्य एजेंट से भिन्न हो और जिस पर पैराग्राफ 5 लागू होता है) प्रयोजनलिखित राज्य में स्थायी संस्थापन माना जाएगा, यदि:

- (क) उसे प्रयोजनलिखित संविदाकारी राज्य में उस उद्यम के लिये अथवा उसके नाम से संविदाएं सम्पन्न करने का अधिकार है और प्रायः उसका प्रयोग करता है, जब तक कि उसकी गतिविधियां उस उद्यम के लिए मास अथवा तिजारती मास खरीदने तक ही सीमित न हों;
- (ख) वह प्रयोजनलिखित संविदाकारी राज्य में प्रायः उस उद्यम के मास अथवा तिजारती मास का स्टॉक रखता हो जिसमें से वह उद्यम की ओर से नियमित रूप से मास अथवा तिजारती मास की डिलीवरी करता है; अथवा
- (ग) वह, प्रयोजनलिखित राज्य में, समग्रतः अथवा लगभग समग्रतः उद्यम के लिए अथवा उस उद्यम के लिए और अन्य उद्यमों के लिये, जो उससे नियंत्रित होते हों अथवा जिनका उसमें नियंत्रित हित हो, प्रायः आदेश प्राप्त करता हो।

5. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल इसलिए कोई स्थायी संस्थापन होता नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, जहाँ ऐसे व्यक्ति अपना कारोबार सामान्य रूप से कर रहे हों। यह वहां लागू नहीं होगा जहाँ ऐसा दलाल या एजेंट उस दूसरे राज्य में पैराग्राफ 4 में वर्णित कार्यकलापों को पूर्णतः अथवा प्रायः पूर्णतः स्वयं उस उद्यम के लिए अथवा उस उद्यम के लिए और दूसरे उद्यमों के लिए जो उससे नियंत्रित होते हों अथवा जिनका उसमें नियंत्रित हित हो, करता हो।

6. यह तथ्य कि कोई कंपनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसा कारोबार को नियंत्रित करती है अथवा उससे नियंत्रित होती है

है जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, अथवा जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार करती है, उन दोनों में से कोई भी कंपनी स्वतः ही दूसरी कंपनी का स्थायी संस्थापन नहीं बन जाएगी।

7. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के बीमा उद्यम का, पुनर्बीमा के मामलों को छोड़कर, दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन होना समझा जाएगा, यदि वह उस राज्य के राज्यक्षेत्र के अंदर बीमा की किस्में वसूल करता है या किसी कर्मचारी के जरिये अथवा किसी प्रतिनिधि के जरिये, जो उस अनुच्छेद के पैराग्राफ 5 के अर्थों में स्वतंत्र हैसियत का एजेंट नहीं है, वहां स्थित ओब्लिग का बीमा करता है।

अध्याय III

आय का कराधान

अनुच्छेद 6

अचल संपत्ति से आय

1. अचल संपत्ति (जिसमें कृषि और वन-संपत्ति से आय शामिल है) से प्राप्त आय पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसमें ऐसी संपत्ति स्थित हो।

2. "अचल संपत्ति" पद का अर्थ वह होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार उसका अर्थ होता है जिसमें संबंधित संपत्ति स्थित है। इस पद में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे—अचल संपत्ति के उप साधन के रूप में संपत्ति, कृषि और वन-विज्ञान में प्रयुक्त पशु-धन तथा उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-संपत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल संपत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भण्डार, स्रोत, तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संवाहन के लिए अथवा कार्य कहने के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अवधियों के अधिकार; स्रोत तथा अग्र प्राकृतिक संसाधन, जल-यान, नौकाएं तथा विमान अचल संपत्ति नहीं माने जाएंगे।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध अचल संपत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, किराये पर देने, अथवा किसी अन्य प्रकार के उपयोग से होने वाली आय पर लागू होंगे।

4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध, किसी उद्यम की अचल संपत्ति से होने वाली आय पर तथा स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के निष्पादन के लिए इस्तेमाल में आने वाली अचल संपत्ति से होने वाली आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद 7

कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की आय अथवा लाभ पर कर केवल उस राज्य में ही लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार नहीं चलाता हो। यदि उद्यम पूर्वोक्त प्रकार से कारोबार कर रहा हो, तो उद्यम की आय अथवा लाभ पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा परन्तु केवल उसी ही आय और लाभ पर कर लगाया जा सकेगा जो निम्नलिखित के कारण हुए माने जा सकते हैं।

(क) उस स्थायी संस्थापन ;

(ख) उस दूसरे राज्य में वैसे ही अथवा उसी प्रकार के माल अथवा निवारणी माल की विधियों जैसे कि उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से बेचे जाते हैं ; अथवा

(ग) उस दूसरे राज्य में किये गये वैसे ही अथवा उसी प्रकार व्यावसायिक कार्य जैसे उस स्थायी संस्थापन के माध्यम किये जाते हैं।

2. जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उसमें कारोबार करता है ; वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में उस स्थायी संस्थापन के कारण उगको उस आय और लाभ का होना माना जाएगा जिसके प्राप्त होने का अपेक्षा तब रहती जब वह उन्हीं अथवा वैसे ही परिस्थितियों के अंतर्गत, उन्हीं अथवा वैसे ही कार्यों में लगा हुआ कोई निश्चित अथवा अग्र उद्यम होगा, और जिस उद्यम का वह स्थायी संस्थापन है उसके साथ संपूर्णतः स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता है।

3. किसी स्थायी संस्थापन की आय और लाभों के निर्धारण में उन व्ययों को कटौतियों के रूप में स्वीकृति दी जाएगी, जो स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनों के लिए किये गये हों, जिनमें इस प्रकार किये गये कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय शामिल रहेंगे, चाहे वे उस राज्य में किये गये हों, जहां स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यथा

4. जहां तक इस बात का संबंध है कि किसी संविदाकारी राज्य में किसी उद्यम की कुल आय और लाभों की उद्यम का गठन प्राप्तियों व कुछ प्रतिशत-अनुपात के आधार पर वा विभिन्न अंशों में अनुभाजन के आधार पर, किसी स्थायी संस्थापन के कारण माने जाने वाली आय और लाभों को निश्चित करने की प्रथा हो, वहां इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 की कोई भी व्यवस्था उस संविदाकारी राज्य को ऐसी यथावधि अनुसूचना पद्धति से कर लगाने योग्य आय तथा लाभों को निर्धारित करने से नहीं रोकती ; तथापि, अपनाई गई अनुभाजन पद्धति ऐसी होनी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में निहित निष्कर्षों के अनुसार होगा।

5. कोई आय या लाभ केवल इस कारण स्थायी संस्थापन को हुए नहीं माने जायेंगे कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के लिए माल अथवा तिजारती वस्तुएं खरीदी जाती हैं।

6. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनों के लिए, स्थायी संस्थापन के कारण माने जाने वाली आय और लाभों का तब तक उमा पद्धति से वर्षानुवर्ष निर्धारित किया जाएगा जब तक कि उसके विपरीत कोई उपयुक्त तथा पर्याप्त कारण न हो।

7. जहां आय और लाभ में आय की वे मदें शामिल हों, जिनका इस अभिसमय के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद 8

जहाजरानी तथा विमान परिवहन

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की अंतर्राष्ट्रीय यातायात में विमान परिवहन से होने वाली आय पर कर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही लगेगा।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की, अंतर्राष्ट्रीय यातायात में जलयानों के परिवहन से होने वाली आय पर कर दूसरे संविदाकारी राज्य में लगाया जा सकेगा, लेकिन उस दूसरे संविदाकारी राज्य में लगाये गये कर में से उसकी 50 प्रतिशत राकम कम कर दी जाएगी।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध किसी पूल, संयुक्त कारोबार अथवा वायुयान तथा जलयानों के परिवहन में लगी किसी अंतर्राष्ट्रीय परिवहन एजेंसी के भाग लेने से प्राप्त होने वाली आय पर भी लागू होंगे।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के प्रयोजनों के लिये, अंतर्राष्ट्रीय यात्रायात में जलयानों अथवा विमानों के परिचालन से संबंधित निधियों पर ब्याज को ऐसे जलयानों अथवा विमानों के परिचालन से होने वाली आय माना जाएगा।

5. "जलयान अथवा विमान परिवालन" पद का अर्थ होगा जलयानों अथवा विमानों से व्यक्तियों, डाक, पशु-धन, अथवा माल के लाने-ले जाने का कारोबार, जिसमें जलयानों अथवा विमानों का आकस्मिक पट्टा तथा इस प्रकार के परिवहन से प्रत्यक्षतः संबंधित अन्य कोई भी गतिविधि शामिल है।

अनुच्छेद 9

सम्बद्ध उद्यम

जहां :

(क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम, दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा परोक्षतः भाग लेता है, अथवा

(ख) वे ही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा परोक्षतः भाग लेते हैं,

और दोनों ही मामलों में, दोनों उद्यमों के बीच वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखीं अथवा लगाई जाती हैं जो वैसी शर्तों से भिन्न हैं जैसी स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं, वहां ऐसे कोई लाभ जो, उन शर्तों के नहीं होने की हालत में, उन उद्यमों में से किसी एक उद्यम को प्राप्त हुए होते, किन्तु उन शर्तों के कारण प्राप्त नहीं हुए तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में सम्मिलित किये जा सकेंगे तथा उन पर तदनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 10

लाभांश

1. किसी कंपनी द्वारा, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा किये गये लाभांश पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. लेकिन, इस प्रकार के लाभांश पर उस संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा जिसकी लाभांश अदा करने वाली कंपनी निवासी है, तथा यह कर उस राज्य के कानून के अनुसार लगाया जाएगा परन्तु यदि लाभांश का हितभागी स्वामी कोई ऐसी कंपनी है जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, तो इस प्रकार लगाये जाने वाले कर की रकम निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी :—

(क) जिस मामले में लाभांश अदा करने वाली कंपनी किसी औद्योगिक उपक्रम में कार्यरत हो और लाभांश की हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य की कंपनी हो, जिसके पास लाभांश अदा करने वाली कंपनी के कम से कम 10 प्रतिशत मत-धिकार शेयर हों, वहां लाभांश की सकल रकम का 15 प्रतिशत ;

उपपैराग्राफ (क) के अधीन नहीं आने वाले मामले में, लाभांश की सकल रकम का 20 प्रतिशत यदि लाभांश करने वाली कंपनी किसी औद्योगिक उपक्रम में कार्यरत हो अथवा यदि लाभांश का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य की कंपनी है जिसके पास लाभांश अदा करने वाली कंपनी के कम से कम 25 प्रतिशत मत-धिकार शेयर हैं।

3. (क) इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "लाभांश" पद का अर्थ है ऐसे शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय जो ऋण-दावे नहीं हों, लाभों में शामिल हो तथा अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त वह आय है जो उन संविदाकारी राज्य के कराधान कानून के अनुसार शेयरों से प्राप्त आय में समाहित हो जिसकी वितरण करने वाली कंपनी निवासी हो।

(ख) इस अनुच्छेद में "औद्योगिक उपक्रम" पद का अर्थ निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में आने वाला उपक्रम है :

- (1) विनिर्माण, संयोजन और संसाधन ;
- (2) निर्माण, सिविल इंजीनियरी और जलयान निर्माण ;
- (3) बिजली, जल-शक्ति अथवा गैस का उत्पादन अथवा पानी की सप्लाई ;
- (4) कृषि, वानिकी, मछली-पालन और बागान ;
- (5) औद्योगिक निवेश के संवर्धन से संबंधित दोनों ही संविदाकारी राज्यों के कानूनों के अंतर्गत दिये गये विशेषाधिकारों का हकदार कोई भी अन्य उपक्रम ; और
- (6) कोई भी अन्य उपक्रम जिसे उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ "औद्योगिक उपक्रम" घोषित किया जाए जिसमें वह उपक्रम स्थित है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कंपनी निवासी है, वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यापार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित एक निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं सम्पन्न करता है और जिस धारिता के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा 14 के उपबंध यथास्थिति लागू होंगे।

5. जहां कोई कंपनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहां वह दूसरा राज्य कंपनी द्वारा अदा किये गये लाभांशों पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाएगा जहां तक कि उस दूसरे राज्य के निवासी को ऐसे लाभांश अदा नहीं किये जाते अथवा जहां तक कि जिस धारिता के संबंध में इस प्रकार के लाभांश अदा किये जाते हैं वे उस राज्य में स्थित एक स्थायी संस्थापन अथवा एक निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध नहीं हों, और न ही कंपनी के अवितरित लाभों पर अवितरित लाभों संबंधी कर लगाया जाएगा चाहे अदा किये गये लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में ही हों।

अनुच्छेद 11

ब्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा किये जाने वाले ब्याज पर कर उस दूसरे राज्य में लगाया जाएगा।

2. लेकिन, ऐसे ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसमें यह उत्पन्न होता है, लेकिन इस प्रकार लगाया गया कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा :—

(क) ब्याज की सकल रकम का 10 प्रतिशत यदि यह किसी वित्तीय संस्था द्वारा (जिसमें बीमा कंपनी शामिल है) प्राप्त की गयी हो ;

(ख) अन्य सभी मामलों में, ब्याज की सकल रकम का 25 प्रतिशत।

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी, किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले व्याज पर उस राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी, यदि—

- (क) व्याज का प्राप्तकर्ता सरकार, स्थानीय प्राधिकरण अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य का केन्द्रीय बैंक हो ; अथवा
- (ख) व्याज की अदायगी किसी भी एजेंसी अथवा संस्था को की जाती है, जिसमें कोई वित्तीय संस्था भी शामिल है, जिसके संबंध में इस पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के संक्षेप प्राधिकारियों की सहमति ली जाएगी।

4. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त “व्याज पद” से अभिप्रेत है प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय चाहे वे बंधक-पत्र द्वारा प्रतिभूत की गई हों अथवा नहीं और चाहे उनको ऋणदाता के लाभों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं, और खासकर, सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय तथा बंध-पत्रों अथवा ऋण-पत्रों से प्राप्त आय, जिनमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंध-पत्रों अथवा ऋण-पत्रों के संबंध में प्रदान किये जाने वाले प्रीमियम और पुरस्कार और उस संविदाकारी राज्य के कराधान कानून के अंतर्गत व्याज पर दी गई रकम से होने वाली आय शामिल है जिसमें आय उद्भूत होती है।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि व्याज देने वाला, एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें व्याज उत्पन्न हुआ हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यापार चलाता हो अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता हो और जिस ऋण-दावे के संबंध में व्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित हो। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, यथास्थिति, लागू होंगे।

6. किसी संविदाकारी राज्य में व्याज तब उद्भूत हुआ माना जाएगा जब व्याज अदा करने वाली स्वयं वह संविदाकारी राज्य, कोई राजनैतिक उपमंडल, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। किन्तु, जहां व्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो या नहीं, संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान है जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था जिस पर व्याज की अदायगी की गई हो, और इस प्रकार का व्याज उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है, तब इस प्रकार का व्याज उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहां व्याज अदा करने वाले तथा पाने वाले के बीच अथवा उन दोनों के बीच और किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण, अदा की गई व्याज की रकम, उस ऋण दावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए व्याज की रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है जिसके लिए इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम-वर्णित रकम पर लागू होंगे। उस मामले में, अदायगी का अतिरिक्त भाग इस अभिसमय के अन्य उपबंधों का अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगने योग्य रहेगा।

अनुच्छेद 12

रायल्टियां

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की जाने वाली रायल्टियों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. लेकिन, ऐसी रायल्टियों पर उस संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा जिसमें वे उद्भूत होती हैं, लेकिन इस प्रकार लगाया गया कर रायल्टियों की सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त “रायल्टियां” शब्द से साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृतियों (जिसमें चलचित्र फिल्मों, फोनोग्राफिक रिकार्डों अथवा रेडियो या दूरदर्शन प्रसारण के लिए फिल्मों अथवा टेप शामिल हैं) के किसी भी प्रतिलिप्यधिकार, किसी भी पेटेंट, ट्रेड मार्क, डिजाइन अथवा माडल, प्लान, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के प्रतिकूल के रूप में अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए अथवा औद्योगिक वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी के लिए प्राप्त किसी प्रकार की अदायगी अभिप्रेत है।

4. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंध उस हालत में लागू नहीं होंगे। यदि रायल्टी का प्राप्तकर्ता, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें रायल्टियां उद्भूत होती हैं, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यापार चलाता है अथवा उस दूसरे राज्य में, उसमें स्थित किसी निश्चित स्थान से, स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है, तथा जिस अधिकार अथवा संपत्ति के बारे में रायल्टियों की अदायगी की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा 14 के उपबंध यथास्थिति लागू होंगे।

5. किसी संविदाकारी राज्य में रायल्टियां उद्भूत हुई तब मानी जाएंगी, जब रायल्टी अदा करने वाला स्वयं वह राज्य, कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। परन्तु जहां रायल्टियां अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान है जिसके संबंध में रायल्टी अदा की गई थी, और इस प्रकार की रायल्टियां उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हैं तब ऐसी रायल्टियां उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएंगी जिसमें स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

6. जहां रायल्टी अदा करने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच अथवा उन दोनों के और किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण, अदा की गई रायल्टियों की रकम, उसके ऐसे प्रयोग, अधिकार अथवा सूचना को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए वे रायल्टियां अदा की जाती हैं, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके लिए इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। उस मामले में, अदायगियों के अधिभाग पर इस अभिसमय के अन्य उपबंधों का अनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 13

पूँजीगत लाभ

1. अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथापरिभाषित अचल संपत्ति के अन्तरण से हुए लाभों पर, उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसमें ऐसी संपत्ति स्थित है।

2. चल संपत्ति, जो एक संविदाकारी राज्य के उपक्रम के स्थायी संस्थापन की उस व्यापारिक संपत्ति के अंग के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित है, अथवा एक संविदाकारी राज्य के निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ उपलब्ध निश्चित स्थान से संबंधित चल संपत्ति के अन्तरण से हुए लाभों

पर जिसमें ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा संपूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले लाभ भी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

3. पैरा 2 के उपबन्धों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम को उन जलयानों अथवा वायुयानों के अंतरण से प्राप्त होने वाले लाभों पर जो उसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में चलाये जाते हैं, अथवा ऐसे जलयानों या वायुयानों के परिचालन से संबंधित चल संपत्ति के अंतरण से प्राप्त होने वाले लाभों पर उस राज्य में कर लग सकेगा।

4. किसी संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा ऊपर पैराग्राफ 1, 2 और 3 तथा अनुच्छेद 12 में उल्लिखित संपत्ति से भिन्न किसी संपत्ति के अंतरण से प्राप्त लाभ पर कर केवल उसी राज्य में लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद 14

स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा इसी प्रकार की अन्य स्वतंत्र सेवाओं के संबंध में अर्जित आय पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा जब तक कि ऐसे कार्य कलाप दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किए जाते। व्यावसायिक सेवाओं अथवा स्वतंत्र कार्य कलापों से होने वाली आय के संबंध में, जो उसे दूसरे राज्य के अन्तर्गत किए जाते हैं, उस दूसरे राज्य द्वारा कर लगाया जा सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में की जा रही व्यावसायिक सेवाओं या अन्य स्वतंत्र कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय दूसरे राज्य में कर लगने योग्य नहीं होगी, यदि :

(क) प्राप्तकर्ता संगत "पिछले वर्ष" या "कर वर्ष" में, जैसा भी मामला हो, कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक की अवधि या अवधियों के लिए दूसरे राज्य में उपस्थित रहा हो,

(ख) प्राप्तकर्ता ऐसे वर्ष में, कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक की अवधि या अवधियों के लिए दूसरे राज्य में कोई निश्चित स्थान नहीं रखता है, और

(ग) आय उस दूसरे राज्य में स्थित किसी उद्यम अथवा स्थायी संस्थापन द्वारा वहन नहीं की जाती है।

3. "व्यावसायिक सेवाएं" पद में विशेष रूप से स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षणिक या अध्यापन संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों, सर्जनों, धकीलों, इंजीनियरों, वास्तुकारों, वस्तु चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप भी शामिल हैं।

अनुच्छेद 15

पराभित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 16, 17, 18, 19, 20 और 21 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए एवं संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर कर केवल उसी राज्य में लग सकेगा जब तक कि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया जाता हो। यदि इस प्रकार नियोजन किया जाता है, तो उससे प्राप्त ऐसे पारिश्रमिक पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा, दूसरे संविदाकारी राज्य में किये गये नियोजन

के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर कर केवल प्रथमोलिखित राज्य में ही लगेगा, यदि :

(क) प्राप्तकर्ता, संगत "पिछले वर्ष" अथवा "कर वर्ष" में, जैसा भी मामला हो, कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक की अवधि अथवा अवधियों के लिए दूसरे राज्य में मौजूद रहा है, और

(ख) पारिश्रमिक की अवधायी ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से की गई हो, जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है, और

(ग) पारिश्रमिक दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा अथवा किसी ऐसे स्थायी संस्थापन या निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है जो नियोजक का दूसरे राज्य में है।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबन्धों के होते हुए भी, किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में परिचालित जलयान अथवा वायुयान पर किए गए नियोजन के संबंध में मिलने वाले पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लग सकेगा।

अनुच्छेद 16

निदेशकों की फीस और उच्चतर के प्रबंधकीय अधिकारियों का पारिश्रमिक

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी ऐसी कंपनी के निदेशक मंडल के एक सदस्य की हैसियत से, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, प्राप्त निदेशक की फीस तथा उसी प्रकार की अदायगियों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कंपनी के उच्चस्तरीय प्रबंध अधिकारी की हैसियत में प्राप्त किये जाने वाले वेतन, मजदूरी और उसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

अनुच्छेद 17

कलाकार और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबन्धों के होते हुए भी, लोक मनोरंजनकर्ताओं, जैसे थियेटर, चलचित्र, रेडियो अथवा दूरदर्शन कलाकार तथा संगीतज्ञ और खिलाड़ियों को अपने इस प्रकार के वैयक्तिक कार्यों से प्राप्त आय पर उस संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा, जिसमें ऐसे कार्य किए जाते हैं।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपनी इस प्रकार की हैसियत में किए गए वैयक्तिक क्रियाकलापों के संबंध में प्राप्य आय स्वयं मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, वहां उस आय पर, अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबन्धों के होते हुए भी, उस संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा ऐसे क्रियाकलाप किए जाते हैं।

3. अनुच्छेद 7 के उपबन्धों के होते हुए भी, जहां इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित कार्यकलाप एक संविदाकारी राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा किए जाते हैं वहां ऐसे उद्यम द्वारा किए गए ऐसे कार्यकलापों से प्राप्त लाभों पर प्रथमोलिखित संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा, जब तक कि उस उद्यम को ऐसे कार्यकलापों की व्यवस्थाओं के संदर्भ में दूसरे संविदाकारी राज्य की सार्वजनिक निधियों द्वारा जिसमें उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, स्थानीय प्राधिकरण या सांविधिक निकाय शामिल है, पर्याप्त रूप से सहायता नहीं दी गई हो।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध सार्वजनिक मनोरंजनकलाओं अथवा खिलौनों द्वारा एक संविदाकारी राज्य में किए गए कार्यक्रमों से प्राप्त लाभ, वेतन, मजदूरी और इसी प्रकार की आय के पारिश्रमिक पर लागू नहीं होंगे यदि उस संविदाकारी राज्य के दोरे के संबंध में दूसरे संविदाकारी राज्य की सार्वजनिक निधियों द्वारा पर्याप्त रूप से सहायता की जाती है जिनमें उसका कोई भी राजनैतिक उप-प्रभाग, स्थानीय प्राधिकरण अथवा सांविधिक निकाय शामिल है।

अनुच्छेद 18

सरकारी कार्य

1. एक संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति को, जो उस राज्य का नागरिक है, दूसरे संविदाकारी राज्य में सरकारी कार्यों को निभाने में दी गई सेवाओं के लिए दिए गए पारिश्रमिक (जो पेंशन नहीं है) पर केवल प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा।

2. संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को दी गई पेंशन पर उसी संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध, संविदाकारी राज्यों में से किसी भी राज्य की सरकार द्वारा लाभार्थ बनाए गए कारोबार के संबंध में की गई सेवाओं से संबंधित पारिश्रमिक और पेंशनों पर लागू नहीं होंगे।

4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, "सरकार" शब्द में दोनों संविदाकारी राज्यों की कोई भी राज्य सरकार अथवा स्थानीय अथवा सांविधिक प्राधिकरण, और विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक तथा बैंक ऑफ वाइलैण्ड शामिल होंगे।

अनुच्छेद 19

गैर सरकारी पेंशनों तथा बाणिकियां

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के आन्तरिक स्रोतों से प्राप्त हुई (अनुच्छेद 18 में उल्लिखित पेंशन से भिन्न) किसी पेंशन या बाणिकी पर कर केवल प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में ही लगाया जा सकेगा।

2. "पेंशन" शब्द का अर्थ उस नियत-कालिक भुगतान से है जो विगत समय में की गई सेवाओं के प्रतिफल के रूप में या सेवाओं के निष्पादन के दौरान शारीरिक चोट की क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त किया जाता हो।

3. "बाणिकी" शब्द का अर्थ उस उल्लिखित राशि से है, जो धन अथवा धन के मूल्य में पर्याप्त अथवा पूरे प्रतिफल के लिए, अदायगियां करने के किसी दायित्व के अधीन, जीवन-पर्यन्त अथवा विनिश्चित अथवा निश्चित समावधि के दौरान उल्लिखित समय पर देय हो।

अनुच्छेद 20

विद्यार्थी और प्रशिक्षु

किसी विद्यार्थी या व्यावसायिक प्रशिक्षु को, जो एक संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तत्काल पूर्व दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है या था और जो मातृ अपनी शिक्षा या प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में उपस्थित है, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में निम्नलिखित पर कर से छूट प्राप्त होगी :

(क) उसके भरण-पोषण शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ अनुदान भत्ता या पुरस्कार;

(ख) उसके भरण-पोषण, शिक्षा या प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य से बाहर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा उसे की गई अदायगियां; और

(ग) किसी भी "पिछले वर्ष" या "कर वर्ष", जैसी भी स्थिति हो के दौरान प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में नियोजन से प्राप्त पारिश्रमिक पर, जो 15,000 रु. या थोड़ी मुद्रा में उसके समतुल्य की राशि से अधिक न हो, अर्थात् कि ऐसा, नियोजन उसके अध्ययन से सीधा संबंधित हो अथवा उसके भरण-पोषण के प्रयोजनार्थ किया जाता हो।

अनुच्छेद 21

प्राध्यापक, अध्यापक और शोध छात्र

1. किसी प्राध्यापक, अध्यापक अथवा शोध छात्र को, जो किसी विश्व विद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय अथवा अन्य अनुमोदित संस्था में अध्यापन अथवा शोध कार्य के प्रयोजनार्थ अथवा दोनों कार्यों के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय अथवा अनुमोदित संस्था के निमन्त्रण पर उस दूसरे राज्य का दौरा करने के तुरन्त पूर्व संविदाकारी राज्यों में से एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था, ऐसे अध्यापन अथवा शोध कार्य के लिए प्राप्त किसी भी पारिश्रमिक पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके पहुँचने की तारीख से दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कर से छूट प्राप्त होगी।

2. यह अनुच्छेद शोधकार्य से प्राप्त आय पर ही लागू होगा, यदि ऐसा शोध-कार्य व्यक्ति द्वारा अनिवार्य के लिए किया जाता है और प्रधान-तया किसी अन्य गैर सरकारी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के लाभ के प्रयोजनार्थ नहीं किया जाता है।

3. इस अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 20 के प्रयोजनार्थ, किसी व्यक्ति को एक संविदाकारी राज्य का निवासी तब समझा जाएगा, यदि वह उस संविदाकारी राज्य में, जिस वर्ष में वह दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता है उस "पूर्ववर्ती वर्ष" अथवा "कर वर्ष", जैसी भी स्थिति हो, में अथवा तत्काल "पूर्ववर्ती वर्ष" अथवा "कर वर्ष" में उस संविदाकारी राज्य का निवासी रहा हो।

4. पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ, "अनुमोदित संस्था" का अर्थ एक ऐसी संस्था से है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अनुमोदित किया गया हो।

अनुच्छेद 22

अन्य आय

किसी संविदाकारी राज्य के निवासी की आय की मरदों पर, जहाँ कहीं उद्भूत होती हों, जिन्हें इस करार के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं किया गया है, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा। आय की ऐसी मरदों पर उस संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा जहाँ ऐसी आय उद्भूत होती है।

अध्याय—4

बोहरे कराधान के अपाकरण की गढ़तियां

अनुच्छेद 23

बोहरे कराधान का अपाकरण

1. दोनों संविदाकारी राज्यों में लागू कानून अपने-अपने संविदाकारी राज्यों में आय के कराधान को शासित करते रहेंगे, जब तक कि इस अभिसमय में उनके प्रतिकूल कोई उपबन्ध नहीं बनाये जाते।

2. भारत के किसी निवासी द्वारा वाइलैण्ड में प्राप्त होने वाले लाभों अथवा आय के संबंध में, जिस पर भारत और वाइलैण्ड दोनों में कर लगाया गया है, वाइलैण्ड के कानूनों के अन्तर्गत और इस अभिसमय के उपबन्धों के अनुसार, प्रत्यक्षतः अथवा कटौती द्वारा देय वाइलैण्ड के

कर की रकम, इस प्रकार के लाभों अथवा आय के संबंध में देय भारतीय कर के प्रति खाता-जमा कर के दी जायेगी, बशर्ते कि किसी ऐसी जमा (ऐसी जमा देने से पूर्व यथासंगणित) भारतीय कर की उस रकम से अधिक नहीं हो, जो आईलैंड में प्राप्त होने वाले लाभों अथवा आय के अनुरूप हो। इसके अलावा, जहाँ निवासी कोई ऐसी कंपनी है, जिसे भारत में अतिकर भ्रष्टा करना है, वहाँ उपर्युक्त जमा प्रथम बार अपनी द्वारा भारत में देय आयकर के प्रति दी जायेगी और शेष रकम, यदि कोई हो, उसके द्वारा भारत में भ्रष्टा किये जाने वाले अतिकर के प्रति जमा दी जायेगी।

3. पैराग्राफ 2 में उल्लिखित खाता-जमा के प्रयोजना के लिये, "आईलैंड का देय कर" पद में ऐसी कोई भी रकम शामिल मानी जायेगी जो किसी भी वर्ष के लिये आईलैंड के कर के रूप में देय रही हो, यदि उस वर्ष के लिये अथवा उसके किसी भाग के लिये, निवेश प्रवर्धन अधिनियम (बी.ई. 2520) के उपबन्धों अथवा राजस्व संहिता (बी.ई. 2481) के अन्तर्गत जो आईलैंड में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये बनायी गयी है अथवा जिन्हें इसके पश्चात् आईलैंड में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये विद्यमान कानूनों में संशोधन करके अथवा उनके अलावा लागू किया जा सकेगा, के अन्तर्गत कर में कोई छूट अथवा कटौती नहीं दी गयी हो।

4. आईलैंड के किसी निवासी द्वारा, भारत के कानून के अन्तर्गत इस अभिसमय के उपबन्धों के अनुसार, भारत में प्राप्त होने वाले लाभों और आय में प्रत्यक्षतः अथवा कटौती द्वारा देय भारतीय कर की रकम, जिस पर भारत और आईलैंड दोनों में कर लगाया गया है, इस प्रकार के लाभों और आय के संबंध में देय आईलैंड के कर के प्रति खाता-जमा के रूप में दी जायेगी, बशर्ते कि खाता-जमा की ऐसी रकम (ऐसा खाता-जमा देने से पूर्व यथासंगणित) आईलैंड के कर की उस रकम से अधिक न हो, जो भारत में प्राप्त होने वाले लाभों अथवा आय के अनुरूप है।

5. पैरा 4 में उल्लिखित खाता-जमा के प्रयोजन के लिये, "देय भारतीय कर" पद में ऐसी कोई भी रकम शामिल समझी जायेगी जो किसी भी कर निर्धारण वर्ष के लिये भारतीय कर के रूप में देय होती यदि उस वर्ष के लिये अथवा उसके किसी भाग के लिये आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबन्धों के अन्तर्गत विशेष प्रोत्साहन उपायों द्वारा, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये बनाये गये हैं, अथवा जिन्हें इसके पश्चात् भारत में आर्थिक विकास की उत्पत्ति के लिये विद्यमान उपबन्धों में संशोधन करके अथवा इनके अलावा लागू किया जा सकेगा, के अन्तर्गत कर में कोई छूट अथवा कटौती नहीं दी गई हो।

6. जहाँ इस अभिसमय के अन्तर्गत, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य से प्राप्त आय के संबंध में उस संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त हो, तो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य, उस व्यक्ति की शेष आय पर कर की संगणना करने में कर की वही दर लागू करेगा जो इस अभिसमय के अनुसार कर से छूट दी गई आय को छूट नहीं दिये जाने की स्थिति में लागू होती।

अध्याय-5

विशेष उपबन्ध

अनुच्छेद 24

सम-व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य की राष्ट्रियों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसी कोई कराधान व्यवस्था अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जायेगी, जो उस कराधान से और उन संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रियों पर वैसे ही परिस्थितियों में लागू होती है अथवा हो सकती है।

2. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी संस्थान पर लगाया जाने वाला कर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उस कर से अपेक्षाकृत कम अनुकूल नहीं होगा जो उस दूसरे राज्य के वैसे ही कार्यों में प्रवृत्त उद्यमों पर उन्हीं परिस्थितियों में लगाया जाता है।

3. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वे किसी संविदाकारी राज्य को, उस राज्य के निवासी व्यक्तियों को कराधान के प्रयोजनों के लिये कोई ऐसी वैयक्तिक छूटें, राहतें तथा कटौतियाँ प्रदान करने के लिये बाध्य करती हैं, जो कानून द्वारा उस राज्य के निवासी व्यक्तियों को ही उपलब्ध हैं।

4. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिसकी पूंजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कराधान अथवा तत्संबंधी कोई ऐसी अपेक्षा लागू नहीं की जायेगी जो उस कराधान और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य वैसे ही उद्यमों पर उन्हीं परिस्थितियों में लागू होती है अथवा हो सकती है।

5. इस अनुच्छेद में, "कराधान" पद का अर्थ उन करों से है जो इस अभिसमय के विषय हैं।

अनुच्छेद 25

पारस्परिक करार कार्यविधि

1. जहाँ किसी संविदाकारी राज्य का कोई निवासी यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्यवाहियों के कारण उस पर जो कर लगा है अथवा लगाया जायेगा वह इस अभिसमय के अनुरूप नहीं है, तो वह उन राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों द्वारा उपबन्धित उपचारों के होते हुए भी अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है, जिसका वह निवासी है। यह मामला उस कार्य की मूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन वर्षों के अन्तर अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिये जिसके कारण इस अभिसमय के उपबन्धों के अनुरूप कर नहीं लगाया गया है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी उपयुक्त हल पर पहुँचने में असमर्थ हो तो, वह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि से जो इस अभिसमय के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी की परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा।

3. इस अभिसमय की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में यदि कोई कठिनाइयाँ अथवा शंकाएँ उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे उन मामलों में दोहरे कराधान के अपाकरण के लिये परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं। जिनकी इस अभिसमय में व्यवस्था नहीं है।

4. पूर्वोक्त पैराग्राफों के अधिप्राय से सहमति प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं। सहमति होने में जब विचारों का मौखिक-आदान-प्रदान बांछनीय प्रतीत होता हो तो ऐसे आदान-प्रदान किसी द्वायों के माध्यम से किये जा सकते हैं, जिसमें संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि हों।

धनुच्छेद-26

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सख्त प्राधिकारी ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज का आदान-प्रदान करने को इस अधिसमय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये अथवा उन करने के अग्रवर्धन, उनकी घोषावही को रोकने के लिये आवश्यक हैं जो इस अधिसमय के विषय हैं। किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना अथवा दस्तावेज को उसी तरीके से गुप्त समझा जायेगा जैसे कि उस राज्य के अपने कानूनों के अन्तर्गत प्राप्त सूचना और दस्तावेज गुप्त माने जाते हैं और केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों को (जिनमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) प्रकट किया जायेगा जो उन करने के निर्धारण अथवा बसुली, प्रवर्तन अथवा अभियोजन के बारे में अथवा निर्धारण की धीमी से संबंधित है, जो इस अधिसमय के अन्तर्गत पाते हैं। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी इस सूचना अथवा दस्तावेज का केवल ऐसे प्रयोजनों के लिये उपयोग करेंगे। वे इस सूचना अथवा दस्तावेज को सार्वजनिक रूप से स्थायी की कार्यवाहियों में अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे।

2. सूचना अथवा दस्तावेजों का आदान-प्रदान या तो नेमी आधार पर होगा अथवा विशेष मामलों के संदर्भ में अनुसूच पर या दोनों ही प्रकार से किया जा सकेगा। नेमी आधार पर दी जाने वाली सूचना अथवा दस्तावेजों की सूची के संबंध में संविदाकारी राज्यों के सख्त प्राधिकारियों की समय-समय पर सहमति आवश्यक होगी।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबन्धों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित वास्तव शासना नहीं होगा:

- (क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों अथवा प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना;
- (ख) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज देना जो एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं हैं;
- (ग) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज देना, जिससे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा रोजगार संबंधी गुप्त भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सरकार की नीति के प्रतिकूल हो।

धनुच्छेद 27

राजनयिक तथा कौंसली कार्य

इस अधिसमय में निहित किसी भी व्यवस्था पर राजनयिक एजेंटों अथवा कौंसली प्राधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करार के उपबन्धों के अंतर्गत प्राप्त विदेशी विरोधाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अध्याय VII

अंतिम उपबंध

धनुच्छेद 28

प्रवर्तन

1. इस अधिसमय का अनुसमर्थन किया जाएगा तथा अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान-प्रदान बीकाक में मया-संधन शीघ्र किया जाएगा।

2. यह अधिसमय, अनुसमर्थन दस्तावेजों के आदान-प्रदान होने पर लागू होगा और:

- (क) भारत में, जिस वर्ष में अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया जाना है, उस कैलेंडर वर्ष के अगले परवर्ती वर्ष

के जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद प्रारंभ होने वाले "चर वर्ष" में प्राप्त होने वाली छाय के संबंध में;

- (ख) बार्डलैण्ड में, जिस वर्ष में अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया जाता है, उस कैलेंडर वर्ष के अगले परवर्ती वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद प्रारंभ होने वाले "चर वर्षों" अथवा "लिखा अवधियों" में प्राप्त होने वाली छाय के संबंध में, लागू होगा।

धनुच्छेद 29

समाप्ति

यह अधिसमय अनिश्चित काल तक लागू रहेगा, परन्तु संविदाकारी राज्यों में से कोई भी राज्य, इस अधिसमय के लागू होने के वर्ष से पांच वर्षों की समाप्ति के बाद किसी भी कैलेंडर वर्ष में 30 जून को अथवा उससे पहले दूसरे संविदाकारी राज्य को राजनयिक माध्यम से समाप्ति का लिखित नोटिस देकर इस अधिसमय को समाप्त कर सकेगा। ऐसी स्थिति में, यह अधिसमय:—

- (क) भारत में, जिस वर्ष में नोटिस दिया गया हो, उस कैलेंडर वर्ष के अगले परवर्ती वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद प्रारंभ होने वाले "पूर्ववर्ती वर्षों" में प्राप्त होने वाली छाय के संबंध में;
- (ख) बार्डलैण्ड में, जिस वर्ष में नोटिस दिया गया हो, उस कैलेंडर वर्ष के अगले परवर्ती वर्ष के जनवरी मास के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद प्रारंभ होने वाले "चर वर्षों" अथवा "लिखा-अवधियों" में प्राप्त होने वाली छाय के संबंध में;

किप्रभावी हो जाएगा।

जिसके साथ में, इसके लिए अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत् प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस अधिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं।

.....नई दिल्ली.....में वर्ष एक हजार नौ सौ और पच।सं.
.....के.....मास.....मास के
.....बार्डलैण्ड.....दिन को हिंदी, बार्ड और अंग्रेजी
भाषा में, प्रत्येक भाषा की दो-दो और कुल छः मूल प्रतियों में संपन्न
हुआ; ये सभी पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं, लेकिन अर्थ भिन्नता के
मामले में अंग्रेजी पाठ प्रभावी होगा।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

बार्डलैण्ड राज्य की
सरकार की ओर से

एयर ची मार्शल

(विश्वनाथप्रताप सिंह)
वित्त मंत्री

(सिद्धि सधेवसिला)
विदेश मंत्री

दोहरे कराधान के संबंध में बार्डलैण्ड के राज्य और भारत गणराज्य
के बीच हुए अधिसमय की सहमति के बारे में ज्ञापन

यह समझा जाता है कि:

1. इस अधिसमय के धनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 1 (घ) में यथापरि-
भाषित "चर" पद का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसमें किसी ऐसी
राशि की, जो ऐसे करों से संबंधित किसी शुल्क अथवा भूल के बारे में देय
है जिन पर यह अधिसमय लागू होता है अथवा जो इन करने के संबंध
में लगाया गया कोई अर्थव्यवस्था, शामिल नहीं किया जाएगा।

2. इस अधिसमय के धनुच्छेद 10 के पैराग्राफ 5 का यह अर्थ नहीं
लगाया जाएगा कि वह बार्डलैण्ड को, बार्ड रेवेन्यू कोड की धारा 70 जिस
के अनुसार सार्चों के निपटान पर (साक्षियों के रूप में नहीं) कर लगाने
से रोकता है।

3. अनुच्छेद 26 के पैराग्राफ 2 के संदर्भ में, जो सक्षम प्राधिकारियों के बीच हुआ कोई भी करार सविदाकारी राज्यों के अपने-अपने कानूनों में किसी समय-सीमा के होते हुए भी लागू किया जाएगा बशर्त कि ऐसे करार को लागू करने से संबंधित करदाता को लाभ होता हो।

4. यदि बाईलैड किसी देश के किसी निवासी द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में अवधानों के संचालन से प्राप्त होने वाली आय पर कर में उसके 50 प्रतिशत से अधिक की घटौती मंजूर करता है तो, भारत की निवासी जहाजरानी कंपनियों की ऐसी आय पर कर में, पारस्परिकता के आधार पर उतनी ही घटौती मंजूर करने की दृष्टि में, इस अभिसमय के अनुच्छेद 8 के पैरा 2 पर पुनः विचार किया जाएगा।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

बाईलैड राज्य की
सरकार की ओर से

एयर चीफ मार्शल

(विश्वनाथ प्रताप सिंह)
वित्त मंत्री

(सिद्धी सबेत्सिला)
विदेश मंत्री

[फाईल सं. 145/4/71-वि.क.प्र.]

वी. यू. एण्डि, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Foreign Tax Division)

New Delhi, the 27th June, 1986

NOTIFICATION

INCOME TAX

G.S.R. 915 (E) :—Whereas the annexed Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Thailand for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income has been ratified and the instruments of ratification exchanged as required by Article 28 of the said Convention on 13th March, 1986 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and section 24A of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE

CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND FOR

THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Republic of India and
the Government of the Kingdom of Thailand,

DESIRING to conclude a Convention for the
Avoidance of Double Taxation and the Prevention
of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income,

HAVE AGREED as follows :

CHAPTER 1

SCOPE OF THE CONVENTION

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are
residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. This Convention shall apply to taxes on income
imposed on behalf of each Contracting State or of
its political subdivisions or local authorities, irrespec-
tive of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all
taxes imposed on total income, or on elements of
income, including taxes on gains from the alienation
of movable or immovable property, as well as taxes
on the total amounts of wages or salaries paid by
enterprises.

3. The existing taxes to which this Convention
shall apply are :

(a) In the case of India :

(i) the income tax including any surcharge
thereon imposed under the Income-tax
Act, 1961 (43 of 1961) ; and

(ii) the surtax imposed under the Companies
(Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964) ;

(hereinafter referred to as "Indian tax") ;

(b) In the case of Thailand :

(i) the income tax ; and

(ii) the petroleum income tax,
(hereinafter referred to as "Thai tax").

4. The Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 3 of this Article. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of significant changes which have been made in their respective taxation laws.

CHAPTER II

DEFINITIONS

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires :

- (a) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it as well as any other maritime zone referred to in the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and other Maritime Zones Act, 1976 (Act No. 80 of 1976), in which India has sovereign rights and to the extent that these rights can be exercised therein in accordance with international law, as if such maritime zone is a part of the territory of India ;
- (b) the term "Thailand" means the Kingdom of Thailand and includes any maritime area adjacent to the territorial waters of the Kingdom of Thailand which by Thai legislation, and in accordance with international law, has been or may hereafter be designated as an area within which the rights of the Kingdom of Thailand may be exercised ;
- (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean India or Thailand as the context requires ;
- (d) the term "tax" means Indian tax or Thai tax, as the context requires ;
- (e) the term "person" includes an individual, a company and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States ;
- (f) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company or a body corporate under the taxation laws in force in the respective Contracting States ;
- (g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean, respectively, an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State ;
- (h) the term "competent authority" means in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative;

and in the case of Thailand, the Minister of Finance or his authorised representative ;

- (i) the term "national" means any individual possessing the nationality of a Contracting State and any legal person, partnership, association and any other entity deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State ;
- (j) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except where the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State.

2. In the application of the provisions of this Convention by one of the Contracting States, any term not defined herein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has for the purposes of the laws in force in that State relating to the taxes which are the subject of this Convention.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of incorporation, place of management or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting States, then his residential status for the purposes of this Convention shall be determined in accordance with the following rules :

- (a) He shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (hereinafter referred to as his "centre of vital interests") ;
- (b) If the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he does not have a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode ;
- (c) If he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national ;

- (d) If he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

Article 5

Permanent Establishment

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" shall include :

- (a) a place of management ;
- (b) a branch ;
- (c) an office ;
- (d) a factory ;
- (e) a workshop ;
- (f) a mine, a quarry, an oil or gas well or other place of extraction of natural resources ;
- (g) a farm, plantation or other place where agricultural, forestry, plantation or related activities are carried on ;
- (h) a building site or construction or assembly project or supervisory activities in connection therewith, where such site, project or activity continues for the same or a connected project for a period or periods aggregating more than 183 days ;
- (i) a warehouse, in relation to a person providing storage facilities for others ;
- (j) the furnishing of services, including consultancy services, by a resident of one of the Contracting States through employees or other personnel, provided activities of that nature continue (for the same or a connected project) within the other Contracting State for a period or periods aggregating more than 183 days.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include :

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise ;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery ;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise ;

- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise ;

- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research, or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise.

4. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraphs, a person (other than a broker, general commission agent or any other agent of an independent status to whom paragraph 5 applies) acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State, if :

- (a) he has and habitually exercises in the first-mentioned Contracting State, an authority to conclude contracts for or on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise ;
- (b) he habitually maintains in the first-mentioned Contracting State a stock of goods or merchandise belonging to that enterprise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise ; or
- (c) he habitually secures orders in the first-mentioned State wholly or almost wholly for the enterprise or for the enterprise and other enterprises which are controlled by it or have a controlling interest in it.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business. This shall not apply if such broker or agent carries on in that other State an activity described in paragraph 4 wholly or almost wholly for the enterprise itself or for the enterprise and other enterprises which are controlled by or have a controlling interest in it.

6. The fact that a company, which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not, of itself, constitute either company a permanent establishment of the other.

7. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance enterprise of a Contracting State shall, except in regard to reinsurance, be deemed to have a permanent establishment in the other State if it collects premiums in the territory of that State or insures risks situated therein through an employee or through a representative who is not an agent of an independent status within the meaning of paragraph 5 of this Article.

CHAPTER III

TAXATION OF INCOME

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income from immovable property (including income from agriculture or forestry) may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The income for profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the income or profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to—

- (a) that permanent establishment ;
- (b) sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment ; or
- (c) other business activities carried on in that other State of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment.

2. Where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the income or profits which it might be expected to make if it were a distinct that separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In the determination of the income or profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the income or profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of a certain percentage of the gross receipts of the enterprise or on the basis of an apportionment of the total income or profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 of this Article shall preclude that Contracting State from determining the income or profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No income or profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods of merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the income or profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where income or profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

Shipping and Air Transport

1. Income derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in that Contracting State.

2. Income derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships in international traffic may be taxed in the other Contracting State, but the tax imposed in that other Contracting State shall be reduced by an amount equal to 50 per cent thereof.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall also apply to income from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency engaged in the operation of aircraft or ships.

4. For the purposes of paragraphs 1 and 2, interest on funds connected with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as income from the operation of such ships or aircraft.

5. The term "operation of ships or aircraft" shall mean business of transportation of persons, mail, livestock or goods by the ships or aircraft, including the incidental lease of ships or aircraft and any other activity directly connected with such transportation.

Article 9

Associated Enterprises

Where :

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State, and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a company which is a resident of the other Contracting State, the tax shall not exceed—

- (a) 15 per cent of the gross amount of dividends, in a case where the company paying the dividends is engaged in an industrial undertaking and the beneficial owner of the dividends is a company of the other Contracting State owning at least 10 per cent of the voting shares of the company paying the dividends ;
- (b) in the case not covered by sub-paragraph (a) above, 20 per cent of the gross amount of dividends if the company paying the dividends is engaged in an industrial undertaking or if the beneficial owner of the dividends is a company of the other Contracting State owning at least 25 per cent of the voting shares of the company paying the dividends.

3. (a) The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights assimilated to income from shares according to the taxation laws of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident.

(b) In this Article, the term "industrial undertaking" means an undertaking falling under any of the classes mentioned below :

- (i) manufacturing, assembling and processing ;
- (ii) construction, civil engineering and ship-building ;
- (iii) production of electricity, hydraulic power or gas or the supply of water ;
- (iv) agriculture, forestry and fishery and the carrying on of a plantation ;
- (v) any other undertaking entitled to the privileges accorded under the laws of either Contracting State on the promotion of industrial investment; and
- (vi) any other undertaking which may be declared to be an "industrial undertaking" for the purposes of this Article by the competent authority of the Contracting State in which the undertaking is situated.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but the tax so charged shall not exceed :

- (a) 10 per cent of the gross amount of the interest if it is received by any financial institution (including an insurance company) ;

- (b) in all other cases, 25 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if—

- (a) the recipient of the interest is the government, or local authority or the Central Bank of the other Contracting State; or
- (b) the interest is paid to any agency or institution including a financial institution which may be agreed upon for the purposes of this paragraph by the competent authorities of the Contracting States.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures, as well as income assimilated to income from money lent by the taxation laws of the Contracting State in which the income arises.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by that permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them

and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the debt-claims for which it is paid exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12

Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may be taxed in the Contracting State in which they arise, but the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of royalties.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the alienation or the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work (including cinematograph films, phonographic records, and films or tapes for radio or television broadcasting), any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provision of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in

which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of royalties paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

Capital Gains

1. Gains from the alienation of immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment, which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in that other State.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft which it operates in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that State.

4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of any property other than those mentioned in paragraphs 1, 2 and 3 above and Article 12 shall be taxable only in that State.

Article 14

Independent Personal Services

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State unless such activities were

performed in the other Contracting State. Income in respect of professional services or independent activities performed within that other State may be taxed by that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities performed in the other Contracting State shall not be taxable in the other State if .

- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the relevant "previous year" or "tax year" concerned, as the case may be.
- (b) the recipient does not maintain a fixed base in the other State for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in such year, and
- (c) the income is not borne by an enterprise or a permanent establishment situated in that other State.

3. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15

Dependent Personal Services

1. Subject to the provisions of Articles 16, 17, 18, 19, 20 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other Contracting State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if :

- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the relevant "previous year" or "tax year" concerned, as the case may be, and

- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
- (c) the remuneration is not borne by an enterprise of the other Contracting State or by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised abroad a ship or aircraft operated in international traffic, by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State.

Article 16

Directors' Fees and Remuneration of Top-Level Managerial Officials

1. Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in his capacity as an official in a top-level managerial position of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

Artistes and Athletes

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by public entertainers, such as theatre, motion picture, radio or television artistes, and musicians, and by athletes, from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are performed.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of Article 7, where the activities mentioned in paragraph 1 of this Article are provided in a Contracting State by an enterprise of the other Contracting State the profits derived from providing these activities by such an enterprise may be taxed in the first-mentioned Contracting State unless the enterprise is substantially supported by the public funds of the other Contracting State, including any political subdivision, local authority or statutory body thereof, in connection with the provisions of such activities.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply to remuneration or profits, salaries, wages and similar income derived from activities performed in a Contracting State by public entertainers or athletes if the visit to that Contracting State is substantially supported by public funds of the other Contracting State, including any political subdivision, local authority or statutory body thereof.

Article 18

Governmental Functions

1. Remuneration (not being a pension) paid by the Government of a Contracting State to any individual who is a citizen of that State in respect of services rendered in the discharge of governmental functions in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State.

2. Any pension paid by the Government of one of the Contracting States to any individual may be taxed in that Contracting State.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with any business carried on by the Government of either of the Contracting States for the purposes of profit.

4. For the purposes of this Article, the term "Government" shall include any State Government or local or statutory authority of either Contracting State and in particular the Reserve Bank of India and the Bank of Thailand.

Article 19

Non-Government Pensions and Annuities

1. Any pension (other than a pension referred to in Article 18) or annuity derived by a resident of

a Contracting State from sources within the other Contracting State may be taxed only in the first-mentioned Contracting State.

2. The term "pension" means a periodic payment made in consideration of services rendered in the past or as compensation for injuries received in the course of performance of services.

3. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times, during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Article 20

Students and Apprentices

A student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training, shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State on :

- (a) the grant, allowance or award for the purposes of his maintenance, education or training ;
- (b) payments made to him by persons residing outside that first-mentioned Contracting State for the purposes of his maintenance, education or training ; and
- (c) remuneration from employment in that first-mentioned Contracting State, in an amount not in excess of Rs. 15,000 or its equivalent in Thai currency during any "previous year" or "tax year", as the case may be, provided that such employment is directly related to his studies or is undertaken for the purpose of his maintenance.

Article 21

Professors, Teachers and Research Scholars

1. A professor, teacher or research scholar who is or was a resident of one of the Contracting States

immediately before visiting the other Contracting State at the invitation of that other Contracting State or of a university, college, school or other approved institution in that other Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at the university, college, school or other approved institution, shall be exempt from tax in that other Contracting State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his arrival in that other Contracting State.

2. This Article shall only apply to income from research if such research is undertaken by the individual for the public interest and not primarily for the benefit of some other private person or persons.

3. For the purposes of this Article and Article 20, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that Contracting State in the "previous year" or the "tax year", as the case may be, in which he visits the other Contracting State or in the immediately preceding "previous year" or the "tax year".

4. For the purposes of paragraph 1, "approved institution" means an institution which has been approved in this regard by the competent authority of the concerned Contracting State.

Article 22

Other Income

Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not expressly dealt with in the foregoing Articles may be taxed in that State. Such items of income may also be taxed in the Contracting State where the income arises.

CHAPTER IV

METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 23

Elimination of Double Taxation

1. The laws in force in either of the Contracting States shall continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where provisions to the contrary are made in this Convention.

2. The amount of Thai tax payable, under the laws of Thailand and in accordance with the provisions of this Convention, whether directly or by deduction, by a resident of India, in respect of profits or income arising in Thailand, which has been subjected to tax both in India and in Thailand, shall be allowed as a credit against the Indian tax payable in respect of such profits or income provided that such credit shall not exceed the Indian tax (as computed before allowing any such credit) which is appropriate to the profits or income arising in Thailand. Further, where such resident is a company by which surtax is payable in India, the credit aforesaid shall be allowed in the first instance against income tax payable by the company in India and as to the balance, if any, against surtax payable by it in India.

3. For the purposes of the credit referred to in paragraph 2, the term "Thai tax payable" shall be deemed to include any amount which would have been payable as Thai tax for any year but for an exemption or reduction of tax granted for that year or any part thereof under the provisions of the Investment Promotion Act (B. E. 2520) or of the Revenue Code (B. E. 2481) which are designed to promote economic development in Thailand, or which may be introduced hereafter in modification of, or in addition to, the existing laws for promoting economic development in Thailand.

4. The amount of Indian tax payable under the laws of India and in accordance with the provisions of this Convention, whether directly or by deduction, by a resident of Thailand, in respect of profits or income arising in India, which has been subjected to tax both in India and Thailand, shall be allowed as a credit against Thai tax payable in respect of such profits or income provided that such credit shall not exceed the Thai tax (as computed before allowing any such credit) which is appropriate to the profits or income arising in India.

5. For the purposes of the credit referred to in paragraph 4, the term "Indian tax payable" shall be deemed to include any amount which would have been payable as Indian tax for any assessment year but for an exemption or reduction of tax granted for that year or any part thereof by the special incentive measures under the provisions of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), which are designed to promote economic development, or which may be introduced hereafter in modification of, or in addition to, the existing provisions for promoting economic development in India.

6. Where under this Convention a resident of a Contracting State is exempt from tax in that Contracting State in respect of income derived from the other Contracting State, then the first-mentioned Contracting State may, in calculating tax on the remaining income of that person, apply the rate of tax which would have been applicable if the income exempted from tax in accordance with this Convention had not been so exempted.

CHAPTER V

SPECIAL PROVISIONS

Article 24

Non-Discrimination

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances.

3. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to persons not resident in that State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes which are by law available only to persons who are so resident.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected in the same circumstances.

5. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Convention.

Article 25

Mutual Agreement Procedure

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. This case must be presented within three years of the date of receipt of notice of the action which gives rise to taxation not in accordance with the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 26

Exchange of Information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information or documents as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or for the prevention of fraud or eva-

sion of taxes which are the subject of this Convention. Any information or document received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information or document obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information or document only for such purposes. They may disclose the information or document in public court proceedings or in judicial decisions.

2. The exchange of information or document shall be either on a routine basis or on request with reference to particular cases or both. The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the list of the information or documents which shall be furnished on a routine basis.

3. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State ;
- (b) to supply information or documents which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State ;
- (c) to supply information or documents which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information the disclosure of which would be contrary to public policy.

Article 27

Diplomatic and Consular Activities

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreement.

CHAPTER VII

FINAL PROVISIONS

Article 28

Entry into Force

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Bangkok as soon as possible.

2. This Convention shall enter into force upon the exchange of the instruments of ratification and shall have effect :

(a) in India, in respect of income derived during the "previous years" beginning on or after the first day of January of the calendar year next following the calendar year in which the instruments of ratification are exchanged ;

(b) in Thailand, in respect of income derived during "tax years" or "accounting periods" beginning on or after the first day of January of the calendar year next following the calendar year in which the instruments of ratification are exchanged.

Article 29

Termination

This Convention shall remain in force indefinitely but either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving to the other Contracting State, written notice of termination on or before June 30th of any calendar year after the expiration of five years from the year in which the Convention entered into force. In such event, the Convention shall cease to have effect :

(a) in India, in respect of income derived during the "previous years" beginning on or after the first day of January of the calendar year next following the calendar year in which the notice is given ;

(b) in Thailand, in respect of income derived during "tax years" or "accounting periods" beginning on or after the first day of

January of the calendar year next following the calendar year in which the notice is given.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Convention.

Done at New Delhi on this 22nd day of March, one thousand nine hundred and eighty five, in six originals, two each in the Hindi, Thai and English languages, all texts being equally authentic, except in case of divergence when the English text shall prevail.

For the Government of
Republic of India

For the Government of
the Kingdom of Thailand
Air Chief Marshal

(VISHWANATH PRATAP SINGH)

Minister of Finance

(SIDDHI SAVETSILA)
Minister of Foreign Affairs

Memorandum of Understanding with respect to the Double Taxation Convention between the Kingdom of Thailand and the Republic of India

It is understood that :

1. The term "tax" as defined in paragraph 1(d) of Article 3 of this Convention shall be interpreted not to include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Convention applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes.

2. Nothing in paragraph 5 of Article 10 of this Convention shall be construed so as to prevent Thailand from imposing tax on the disposal of profits (not in the form of dividends) in accordance with Section 70 bis of the Thai Revenue Code.

3. With reference to paragraph 2 of Article 26, any agreement reached by the two competent authorities shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic laws of the Contracting

States provided that the implementation of such agreement will be beneficial to the tax-payer concerned.

4. In case Thailand grants reduction from tax of an amount more than 50 per cent thereof on income derived from the operation of ships in international traffic by a resident of any country, paragraph 2 of Article 8 of the Convention shall be reconsidered with a view to granting, on the basis of reciprocity, the same reduction from tax on such income of shipping companies which are residents of India.

For the Government of
Republic of India

For the Government of
the Kingdom of Thailand
Air Chief Marshal

(VISHWANATH PRATAP SINGH)
Minister of Finance

(SIDDHI SAVETSILA)
Minister of Foreign Affairs

[F. No. 145/4/71-FTD]

Notification No. 6780
V. U. ERADI, Jt. Secy.

